8. बोये गए क्षेत्र को क्षति पहुंची	8,353 हैक्टर
9 सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति जैसे सड़कें, पुल, सिंचाई के निर्माण कार्य नगरपालिका की सम्पत्ति, स्कूल आदि, जिसमे औद्योगिक यूनिटें शामिल नही है।	1,063 लाख रु० के मूल्य की

कर्नाटक

1. व्यक्तियो की जाने गई	1
2 गम्भीर रूप से घायल	2
3 क्षतिग्रस्त मकान :	
(1) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त	46
(2) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त	84
योग	130

महाराष्ट्र

1 व्यक्तियों की जाने गई	33
2 क्षतिग्रस्त मकान	219
3 बोए गए क्षेत्र को हुई क्षति	677 हैक्टर
4. नावों की क्षति	91

Aid for Cauvery Delta Project

707. SHRI P. GANGA REDDY. Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Tamil Nadu Government have sought aid for Cauvery Delta Moderation Project; and

(b) if so, the decision of Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): (a) The Cauvery Delta modernisation scheme has not as yet been approved and is pending clearance with Central Water Commission on account of inter State aspects involved on the use of Cauvery waters. No request for any special central assistance for this project has been received in the Centre from the Government of Tamil Nadu.

(b) Does not arise.

राजस्थान में रेगिस्तान के फैलाव पर रोक

708. **श्री लालजी भाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान में रेगिस्तान को बढने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार क्या उपाय कर रही है ,

(ख) क्या इस कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा कोई देश किसी प्रकार की सहायता कररहा है , और

(ग) यदि हा, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस कार्य पर गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्रीय सरकार राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को बढने से रोकने तथा उसके विकास के लिए कई कदम उठा रही है । इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल है :--

(1) अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कमांड

क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में नहरों को पक्का बनाना, सड़कों का निर्माण करना, वनरोपण, क्षेत्र (ग्रान-फार्म) विकास, ग्राम्य जल सप्लाई, आदि शामिल हैं

(2) राजस्थान और गुजरात की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विशेष निधि परियोजना के अन्तर्गत 1971 से 1974 तक राजस्थान के बीकानेर, नागार, चुरू, झुन्झुन और सीकर जिलों मे भूमिगत जल सर्वेक्षण किया गया था ,

(3) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों विशेष निधि परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के घग्गर नदी के बेसिन में 10,005 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भूमिगत जल सर्वेक्षण शुरू किया गया है ,

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना राजस्थान के दस प्रमुख जिलो तथा तीन समीपवर्ती जिलो की छ तहसीलों में चालू है। इन योजनाओं मे कृषि, भूमिगत जल विकास, वन-रोपण, पशु तथा भेड विकास, आदि क्षेत्रो के समेकित विकास की व्यवस्था है,

(5) चालू वर्ष से राजस्थान के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र में सामाजिक वानिकी की केन्द्रीय आयोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में बंजर भूमि तथा सामुदायिक भूमि मे वन-रोपण का विकास करने का विचार है ,

(6) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर, मरु-क्षेत्रों की समस्याओं से सम्बद्ध मदों पर अनुसन्धान कर रहा है, जिसमें बदलते हुये बालू के टीलों के स्थिरीकरण की विधियां, रक्षा-पटटी और वायु-रोधक बनाने, रेंज व्यवस्था, आदि सहित म त्स्य-विज्ञान एवं वन-रोपण की तकनोलोजी शामिल है।

(7) इस सम्बन्ध में राजस्थान नहर परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्माण को गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1975-76 मे अग्रिम योजना सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था की थी।

(ख) जी हा श्रार

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्नलिखित है —

वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दारान राजस्थान नहर परियोजना के कमाड क्षेत्र विकास मे 1,452 00 लाख रुपये खर्च किये गये। परियोजना का कुल अनुमान 1740 लाख डालर है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी का 830 लाख डालर का ऋण भी शामिल है।

गुजरात तथा राजस्थान मे भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंशदान के रूप मे 6 54 लाख डालर तथा भारत सरकार के अंशदान के रूप मे 104 11 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ,

घग्गर नदी के बेसिन में भूमिगत जल के अध्ययन के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास

कार्यक्रम के अंशदान के रूप में 1.67 लाख डालर की राशि स्वीकृत की गई है, जब कि भारत सरकार का अंशदान 176.01 लाख रुपये होगा ।

Business Management in Curriculla of Engineering Colleges and Institutes

709. SHRI NAWAL KISHORE SINHA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state steps taken to introduce Business Management in the Curriculla of Engineering Colleges and Institutes?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): At the first degree level in Engineering courses, elements of Management such as Industrial Organisation and Engineering Management are included in the Curriculum.

The All India Council for Technical Education through its Board of Studies has emphasized the need for appropriate weightage being given to the subject, in Engineering Curriculla.

House-sites for S.C. & S.T.

710. SHRI SAROJ MUKHERJEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the total number of households belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, State-wise who actually got house-sites and the number of such households who could actually build huts on them during the last one year; and

(b) the causes of very slow progress in spite of definite targets fixed by the Central Government for implementation of the Prime Minister's new Economic Programme?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): (a) and (b). As the scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas does not make any distinction between the persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe and those not belonging to these two categories in the matter of allotment of house-sites, no separate statistics regarding the allotment made to the persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe under the scheme are maintained. Of the estimated 113 lakh families without house-sites in the country, about 69 lakh families have already been allotted house-sites by the different State Governments and the Union Territory Administrations. This amounts to more than 60 per cent of the total requirement in the country. Thus, the progress made in the implementation of this scheme is considered satisfactory. The State Governments have been requested to expedite the allotment of house-sites to the remaining families also expeditiously.

Sick Units in Sugar Industry

711. SHRI MOHINDER SINGH GILL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether some new schemes are being finalised to help the sick units in sugar industry in the country;

(b) if so, the amount earmarked for the purpose; and

(c) whether any machinery has also been set up to look into the causes of this sickness?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): (a) A scheme to forestall sickness in selected industries, including the sugar industry, by grant of soft